भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1122

जिसका उत्तर दिनांक 20.12.2018 को दिया जाना है

परमाणु ऊर्जा की जन स्वीकृति हेतु उपाय

1122. श्री जोस.के. मणि :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने यह घोषणा की है कि परमाणु ऊर्जा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को पूरा करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है और संयुक्त राष्ट्र संघ में परमाणु ऊर्जा के प्रति बढ़ते विरोध एवं कुछ देशों द्वारा उनके परमाणु विद्युत संयंत्रों को चरणबद्ध ढंग से बंद किए जाने की योजनाओं के बीच उसने इसकी जन स्वीकृति को बढ़ावा देने हेतु सहायक प्रयासों का सुझाव दिया है ;

(ख) भारत परमाणु रिएक्टरों से कितनी विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है;

(ग) क्या सरकार ने परमाणु उपकरण सुविधा हेतु होल्टेक इंटरनेशनल के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) दिनांक 9 नवंबर, 2018 को आयोजित, संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की 73वीं बैठक में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आईएईए) की रिपोर्ट पर भारत ने कहा कि ऊर्जा की बढ़ी हुई मांग की चुनौती को पूरा करने, जलवायु परिवर्तन से संबंधित चिंताओं और जीवाश्म ईंधन की अस्थिर कीमतों संबंधी समस्या के समाधान तथा ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नाभिकीय ऊर्जा अब भी एक महत्वपूर्ण विकल्प है । इस बात का भी उल्लेख किया गया कि आईएईए को, नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम आरंभ करने वाले या उसका विस्तार करने वाले सदस्य देशों की सहायता वाले अपने कार्यक्रम जारी रखने की आवश्यकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कि वह नाभिकीय ऊर्जा के लिए जनता की स्वीकार्यता बनाने हेतु, सदस्य देशों को, उनकी क्षमता बढ़ाने में सहायता करे ।

(ख) देश में वर्तमान में स्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता 6780 मेगावाट है ।

(ग) नाभिकीय उपस्कर सुविधा के लिए केन्द्र सरकार ने होल्टैक के साथ किसी भी समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किया है ।

(घ) उपरोक्त (ग) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता ।

*****